[श्री चन्द्र पाल शैलानी]

वहां दिल्ली दूरदर्शन का प्रोग्राम नहीं देखा जा सकता क्योंकि यहां की रेंज केवल 68 किलोमीटर है। फलतः इस इलाके के लोग एशियाड 82 और गुट निरपेक्ष सम्मेलन की कार्यवाहियों को दूरदर्शन पर देखने से वंचित रहे। इसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस समारोह व गणतन्त्र दिवस परेड को भी दूरदर्शन द्वारा देखने से वंचित रहते हैं।

सरकार का इरादा आगरा में माइक्रोवेव द्वारा रिले केन्द्र स्थापित करने का है। अतः उसे शीघ्र ही बनाया जाए और दिल्ली में प्रीतमपुरा में जो आर० सी० सी० टावर बनाया जा रहा है, उसे भी जितना जल्दी हो पूरा कराया जाए।

मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि जब तक आगरा में रिले केन्द्र बने या दिल्ली का नया टावर कार्य करे, मथुरा में एक लघु शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर तुरन्त लगाने की कृपा करें ताकि उस क्षेत्र के हजारों उत्सुक दर्शकों की निराशा दूर हो सके।

12.23 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

(iii) Financial assistance to people engaged in Shellac industry for its proper development

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, लाख उद्योग का हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान है। खाद्य उत्पादन, आदिवासी कल्याण और विदेशी मुद्रा की आमदनी से इसका गहरा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। लाख उद्योग अधिकांशतः पिछड़े इलाकों में केन्द्रित है। बिहार में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता हैं। भारत में उत्पन्न लाख का पचास प्रतिशत अकेले छोटा नागपुर से मिलता है। लाख प्रायः बेर, पलास और कुसुम वृक्षों पर उपलब्ध होती है। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लाख उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण रोज़गार की तो इसमें असीमित संभावनायें हैं। लाख उद्योग का समुचित विकास करने पर पर्यावरण सन्तुलन, खाद्य उत्पादन, आदिवासियों की आय वृद्धि और विदेशी मुद्रा अर्जन में मदद मिलेगी। केन्द्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई लाख उत्पादन योजना से लगभग चालीस लाख आदिवासियों को लाभ मिलेगा। इस योजना से ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा। इस योजना से ग्रामवासियों को लाख के वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन में सहायता मिलेगी। लाख का उपयोग दस्तकारी, छपाई की स्याही, औषधियां, श्रंगार प्रसाधन, बिजली के उपकरण, कागज, चूड़ियाँ, चश्मे के फ्रेम आदि विभिन्न चीजों के उत्पादन में किया जाता है। 1981-82 में हमने 490 लाख रुपए का लाख अमरीका को निर्यात किया। लाख का आयात करने वाले अन्य देश है पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, चीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हाँगकांग और मलेशिया। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करती हूं कि वह वाणिज्यिक बैंकों को हिदायत दे कि लाख को उद्योग मानकर ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसके अतिरिक्त रिसर्च, लाख तैयार करने की सस्ती विधि, निर्यात के लिए जहाज में कम भाड़े की दरें और बिचौलियों के शोषण से लाख उप्पादकों को संरक्षण प्रदान किया जाए। आज थाईलैंड से हमारा कड़ा मुकाबला है। केन्द्र सरकार इस दिशा में एकीकृत नीति अपनाए तो इसका निर्यात 18,000 टन अर्थात् तीस करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है।

(iv) Construction of a bridge over the Ganga at Rajghat, Kannauj (U.P.)

श्री छोटे सिंह यादव (कन्नौज): उपाध्यक्ष

महोदय, राजघाट, कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर सेतु बनाना स्वीकृत हुआ है। जिसे सेतु निगम द्वारा बनाना स्वीकार किया गया है। इस पुल के बन जाने से कन्नौज और हरदोई के बीच का मार्ग सुगम हो जाएगा और यहां का सम्पर्क राष्ट्रीय मार्ग (नेशनल हाईवे) से सीधा हो जाएगा। कन्नौज उत्तरी भारत की लम्बे समय तक राजधानी रही है और हिन्दुस्तान के इतिहास में उसका अनूठा एवं गौरवशाली स्थान रहा है। कन्नौज के ही राजा दिल्लु ने दिल्ली नगर को बसाया था, लेकिन उनका मुख्य नगर कन्नौज पूर्णतया उपेक्षित है, जबकि कन्नौज आज भी इत्र के व्यवसाय से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। संबंधित अधिकारीगण इस पुल को तकनीकी कारण बताकर अन्यत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार स्थान परिवर्तन से राजघाट पर पेन्टून (पीपों का पुल) बनाए रखने की आवश्यकता हमेशा के लिए रहेगी, जिसके रख-रखाव पर सरकार को जो लाखों रुपए प्रति वर्ष खर्च करना चालू रखना पड़ेगा और नए स्थान पर पुल बनने से पुल के दोनों ओर पुनः नई सड़क भी बनानी पड़ेगी। इससे सरकार को अधिकतम धनराशि तो व्यय करनी पड़ेगी, पुल बनाने का मुख्य उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा।

अतः सरकार से आग्रह है कि कन्नौज के नाम पर स्वीकृत पुल को कन्नौज में ही राजघाट पर गंगा नदी पर बनाने हेतु संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें और स्थान परिवर्तन की योजना को किसी प्रकार से स्वीकृत न करने का कष्ट करें।

(v) Financial assistance to people affected by recent hail—storin in Gorakhpur (U.P.)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जिले में भयंकर ओलावृष्टि के कारण भीषण क्षति हुई है। ईंट के बराबर के आकार तक के ओले पड़ने के कारण हजारों मकान पूर्णतः नष्ट हो गए हैं और करोड़ों रुपये की फसल बरबाद हो गई है। आम की फसल भी नष्ट हो गई है। ऐसी स्थिति में किसानों के समक्ष भुखमरी का संकट उत्पन्न हो रहा है। अनेक लोग गृहविहीन हो गए हैं।

अतः सरकार से मेरी माँग है कि व्यापक पैमाने पर राहत कार्य आरम्भ किए जायें। लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा किसानों को एवं गरीब लोगों को भुखमरी से बचाने के प्रयत्न किए जायें और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य आरम्भ किए जायें, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। साथ ही किसानों से हर प्रकार की वसूली तत्काल बन्द कर दी जाए और उन्हें छूट भी प्रदान की जाए।

(vi) Drinking Water Scheme from Rajasthan canal to solve drinking water problem in Rajasthan

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त के बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में पीने के पानी की समस्या भयंकर रूप से है।

राज्य सरकार अपने साधनों और केन्द्रीय सरकार की सहायता से पीने के पानी की समस्या को हल करने का अथक प्रयास कर रही है और काफी गाँवों में नलकूपों का निर्माण कर क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के द्वारा पीने का पानी पहुँचा रही है।

मनुष्यों एवं पशुओं द्वारा नलकूपों को पीने का पानी के रूप में लगातार उपयोग